बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 114 ● नई दिल्ली ● शुक्रवार 13 फरवरी 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

शहरी क्षेत्रों में स्कूल खोलने से पहले अब किया जाएगा ये काम, सीएम सैनी ने जारी किए आदेश

चंडीगढ़। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहरी क्षेत्रों में बढ़ती हुई आबादी व क्षेत्र के मध्येनजर बच्चों को शिक्षा मुहैया करवाने के लिए स्कूल खोलने हेतु सर्वे किया जाए ताकि शहरों में बच्चों को लम्बी दूरी तय करके स्कूल न जाना पड़े। मुख्यमंत्री सैनी बुधवार को राज्य स्तरीय दिशा कमेटी की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार, सांसद धर्मबीर सिंह, नवीन जिन्दल सहित कई विधायक भी मौजूद रहे। बैठक से सभी जिला के अधिकारी भी ऑनलाईन जुड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा विभाग द्वारा गत वर्ष स्कूल छोड़ चुके 34 हजार बच्चों में से 18796 बच्चों को 6 माह का प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

कैम्पों में 555 हज आज़मीनों का हुआ टीकाकरण

मुरादाबाद।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा0 कुलदीप सिंह ने बताया है कि राज्य मुख्यालय से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुपालन में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जनपद मुरादाबाद से हज यात्रा पर जाने वाले कुल 1899 हज यात्रियो को जनपद के विभिन्न स्थानों मदरसा जामेउल उल हुदा, गलशहीद, मदरसा नासिर उल उलूम कस्बा कांठ, मदरसा अन्सार उश्शाह फैजुल उलूम, ग्राम मिलक बूजपुर आशा, मूंढापाण्डे में राज्य से नामित हज ट्रेनर देख-रेख में हज टीकाकरण स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा हज टीकाकरण किया जा रहा है टीकाकरण के दौरान समस्त हज यात्रियों को मैनिनजाइटिस, पोलियो की खुराक एवं 65 वर्ष से अधिक उम्र हज यात्रियों को इनफ्लूऐनजा वैक्सीन से आच्छादित किया गया। आज कुल 555 हज यात्रियों का टीकाकरण किया गया। मदरसा जामेउल उल हुदा, गलशहीद, मुरादाबाद में 350 हज यात्रियों का टीकाकरण किया गया। मदरसा नासिर उल उलूम कस्बा काँठ में 86 हज यात्रियों का टीकाकरण किया गया। मदरसा अन्सार उश्शाह फैजुल उलूम, ग्राम मिलक बूजपुर आशा, मूंढापाण्डे में 119 हज यात्रियों टीकाकरण किया गया। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी, मुरादाबाद द्वारा अवगत कराया गया कि आज के टीकाकरण पश्चात अवशेष हज यात्रियों को अब 14 फरवरी को मदरसा जामिया नईमियों, दीवान का बाजार, मदरसा बशीरूल उत कुन्दरकी एवं मदरसा अब्दुल गफ्फूर नईमी, पाकबाडा, 16 फरवरी को मदरसा मदरसा नूरूल कुरान चौराहा गुईयाबाग, मुरादाबाद, ,मदरसा एमए इस्लामियों मौ. लालबाग ठाकुरद्वारा 17 फरवरी को मदरसा जामिया सिद्धिकिया ब्रान्च कार्यालय पीरगैब, निकट राहत पब्लिक स्कूल, निकट पुलिस चैकी मुरादाबाद में हज यात्रियों को टीकाकरण किया जायेगा।

कुन्दरकी के विकास को लेकर मुख्यमंत्री से मिले विधायक

मुरादाबाद।

कुंदरकी विधायक ठाकुर रामवीर सिंह ने आज लखनऊ में मुख्यमत्री योगी आदित्यानाथ ने शिष्टाचार भेंट कर कुंदरकी विधानसभा में अनेक सम्पर्क मार्गों और पुल निर्माण कार्यों को स्वीकृत करने की मांग की। विधायक ने नाज़रपुर से गोविंदपुर कला मार्ग पर स्थित भीकनपुर पुल के क्षतिग्रस्त पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य एवं सुरक्षात्मक कार्य निर्माण, ब्लॉक मुंढापांडेय से कुंदरकी ब्लॉक को जोड़ने वाले जेतिया सादुल्लापुर से जेतिया फिरोजपुर मार्ग पर गागन नदी पर सेतु पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य निर्माण, ग्राम पंचायत भायपुर के मजरा मेमवीनगर घाट बहल्ला नदी पर सेतु निर्माण कार्य, ग्राम पस्सुपुराबाजे व ग्राम किस्वा नगला के बीच नचना नदी पर सेतु निर्माण व पहुंच मार्ग निर्माण, मुरादाबाद गंवा बुलन्दशहर

मार्ग रा'य मार्ग संख्या 148 चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य, एन0एच0 24 दलपतपुर से समदी समदा मुड़िया मल्लूकपुर ईशापुर चन्दनपुर मार्ग पर ड्राई पोर्ट तक पहुंच मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य और ग्राम पंचायत अल्लाहपुर भीकन के कब्रिस्तान से लेकर पंडित नगला के चौराहे तक सड़क निर्माण की मांग की। इसके अतिरिक्त नेशनल हाईवे एन0एच024 डियर पार्क रामनगर मझरा से मिलक अक्का डिलारी, चमरौआ रेलवे फाटक, मुंडिया मल्लूकपुर, मुंडिया घोसियान, भीतखेड़ा, जैतपुर विसाहट से मानपुर पट्टी होते हुए आगापुर नेशनल हाईवे रामपुर तक स्टेट हाईवे निर्माण कार्य खोह नदी व कोसी नदी पर पुल निर्माण सहित अनुमानित लम्बाई ×8 किमी. की स्वीकृति की मांग करते हुए कुंदरकी विधायक ठाकुर रामवीर सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बताया कि क्षेत्र के हजारों ग्रामवासियों को प्रतिदिन मुरादाबाद रामपुर जाना होता है तो रेलवे फाटकों की वजह से कम दूरी तय करने में में भी अत्यधिक समय लगता है तथा जाम की भी समस्या का सामना करना पड़ता है। प्रसव हेतु महिलाओं, परीक्षा देने हेतु छात्र-छात्राओं आदि को जाम की भीषण समस्या से जूझना पड़ता है। उक्त स्टेट हाईवे का निर्माण कराने से रामपुर व मुरादाबाद आने-जाने हेतु दूरी भी कम हो जाएगी तथा जाम व रेलवे फाटकों की समस्या व सड़क दुर्घटनाओं में भी काफी कमी हो जाएगी एवं क्षेत्रवासियों को गंतव्य तक पहुँचने में कम समय लगेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण कराने का आश्वासन दिया। भेंट के दौरान पूर्व सांसद वीर सिंह, ब्लॉक प्रमुख मुंडापांडेय डॉ नवदीप यादव एवं के मिश्रा भी मौजूद रहे।

टीएमयू की अब अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच चोटी किलिमंजारो पर दस्तक

मुरादाबाद। कहते हैं, अगर हौसला बुलंद हो तो कठोर से कठोर लक्ष्य भी आसान होता है। यह कथन जाने-माने पर्वतारोही एवम् पेशे से शिक्षक मनोज कुमार पर सटीक उतरता है। इस पर्वतारोही ने गणतंत्र दिवस पर अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोंच चोटी माउंट किलिमंजारो को फतह कर लिया। यह विशेषकर टीएमयू परिवार के लिए अविस्मरणीय पल रहे, क्योंकि माउंटेनियर मनोज ने तिरंगे के संग-संग टीएमयू का बैनर भी इस सर्वोंच चोटी पर लहराया। माउंट किलिमंजारो पर भी टीएमयू की दस्तक से गदगद कुलाधिपति श्री सुरेश जैन कहते हैं, सामाजिक सरोकारों के प्रति हमारी अगाध आस्था है। जीवीसी मनीष जैन और एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर अक्षत जैन कहते हैं, यह बड़ी उपलब्धि इतिहास में दर्ज हो गई है। यह कहें तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी, तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी की वित्तीय मदद ने माउंटेनियर मनोज कुमार के सपनों में रंग भर दिया है। उल्लेखनीय है, लेफ्टिनेंट कर्नल पूजा नौटियाल भी सामाजिक सरोकार के तहत टीएमयू की आर्थिक मदद से 20 मई 2025 को विश्व की सर्वोंच चोटी- माउंट एवरेस्ट फतह कर चुकी हैं। महंत गुरविंदर सिंह के संग पर्वतारोही मनोज कुमार का यूनिवर्सिटी कैंपस आगमन हुआ, जहां उन्होंने इस उपलब्धि की फोटो कुलाधिपति सुरेश जैन और जीवीसी मनीष जैन को भेंट की। कुलाधिपति ने भी पर्वतारोही को शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया। उल्लेखनीय है, मनोज कुमार शहीद पर्वतारोही रवि कुमार के भाई हैं। माउंटेनियर रवि कुमार ने 20 मई 2017 माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराकर भारत का गौरव बढ़ाया था, लेकिन लौटते समय खराब मौसम के चलते वे शहीद हो गए थे।

मुक़द्दस रमज़ान-दरगाह से मरकज़ी कलेंडर 2026-27 व रमज़ान की जंत्री (सहरी व इफ्तार का टाइम) जारी

बरेली।

मुक़द्दस महीना रमज़ान का आगाज़ 19 या 20 फरवरी को चांद के दीदार के साथ हो जाएगा।

रमज़ान को लेकर मस्जिदों, दरगाहों, खानकाहों,मदरसो और घरों में तैयारियां शुरू हो चुकी है। मस्जिदों में तरावीह के लिए हाफिज़ नियुक्त किये जा रहे है। 18 फरवरी को चांद देखने का एहतमाम किया जाएगा अगर चांद नज़र आ जाता है या कही से शरई शहादत मिल जाती है तो इसी दिन से नमाज़ ए तरावीह शुरू हो जाएगी और अगले दिन 19 फरवरी का रोज़ा होगा। चांद नज़र नहीं आने की सूरत में 20 फरवरी से रमज़ान शुरू हो जाएंगे। मस्जिदों और घरों में रंग-रोगन व साफ-सफाई का काम तेजी से चल रहा है। सहरी व इफ्तार की समय सारिणी (जंत्री) के साथ कलेंडर(2026-27) दरगाह प्रमुख हज़रत मौलाना सुब्हान रज़ा खान (सुब्हानी मियां) व सजादानशीन मुफ्ती अहसन रज़ा क़ादरी(अहसन मियां) ने संयुक्त रूप से जारी कर दिया। जिसमें पहले रोजे से आखिरी रोजे तक सहरी व इफ्तार का वक़्त दर्शाया गया। मुफ्ती सलीम नूरी बरेलवी ने बताया कि जंत्री के अलावा मरकज़ी रेहाने मिल्लत कलैंडर भी जारी किया गया है। जिसमें साल भर होने वाले मुसलमानों के त्यौहार व देश भर में होने वाले प्रमुख उर्स की तारीख भी दर्शायी गयी है। दरगाह के मीडिया प्रभारी नासिर कुरैशी ने बताया कि रोज़ा व इफ्तार की दुआ के अलावा सदक़ा-ए-फित्र, एतेकाफ, तरकीब नमाज़ ईद,फज़ाइल रमज़ान, नमाज़-ए-तरावीह व मकरुआत रोज़ा आदि का मसला भी कलैंडर में दिया गया है।

मरकज़ी रेहाने मिल्लत कलैंडर को देश-विदेश में अक़ीदमंदो व मुरीदों को सोशल मीडिया व डाक द्वारा भेजा जा रहा है। इस मौके पर हाजी जावेद खान, औरंगज़ेब नूरी,परवेज़ नूरी,अजमल नूरी, शाहिद नूरी,ताहिर अल्वी,शान रज़ा, मंजूर रज़ा,मुजाहिद रज़ा, ज़ोहिब रज़ा, साजिद नूरी,इशरत नूरी,इरशाद रज़ा, काशिफ सुब्हानी, युनुस गद्दी, शरिक बरकाती,सबलू अल्वी, अब्दुल माजिद,सुहैल रज़ा, शाद रज़ा, नईम नूरी,सय्यद माजिद, आलेनबी, सय्यद एजाज,आरिफ नूरी, अमान रज़ा,हाजी अज़हर बेग, अजमल रज़ा,समी रज़ा, साकिब रज़ा,तारिक सईद,हाजी शरिक नूरी,अरवाज़ रज़ा आदि लोग मौजूद रहे।

मेजा पुलिस ने 02 वांछित अभियुक्तो को गिरफ्तार कर भेजा जेल

मेजा प्रयागराज।

चोरी से संबंधित 02 वांछित अभियुक्त रवि निषाद पुत्र नेब्बूलाल ,सोनू निषाद पुत्र नेब्बूलाल निवासी ग्राम भटौती थाना मेजा कमि0 प्रयागराज को मुखबिर की सूचना पर भटौती प्लांट तिराहे के पास थाना क्षेत्र मेजा से गिरफ्तार किया गया ।

मेजा पुलिस टीम द्वार दो वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की गई। चोरी से संबंधित 02 वांछित अभियुक्त रवि निषाद पुत्र नेब्बूलाल ,सोनू निषाद पुत्र नेब्बूलाल निवासी ग्राम भटौती थाना मेजा कमि0 प्रयागराज को मुखबिर की सूचना पर भटौती प्लांट तिराहे के पास थाना क्षेत्र मेजा से गिरफ्तार किया गया । नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी । आवेदिका फूलमती पत्नी सुरेश कुमार निषाद नि0 ग्राम समहन बलुहा थाना मेजा प्रयागराज द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र अज्ञात चोरों द्वारा घर का ताला काटकर घर में रखे 02 सिलेण्डर व कुछ गहने व नगदी चोरी कर लेने के संबंध मे तथा महेन्द्र पाल पुत्र शिवनाथ नि0 लूतर थाना मेजा प्रयागराज द्वारा वादी के घर का ताला तोड़कर 02 बक्शे जिनमें रूपये व जेवरात को उठा ले जाने व प्रदीप कुमार पटेल पुत्र स्व0 काक्षन पटेल नि0 भसुन्दर कला थाना मेजा प्रयागराज द्वारा घर के अन्दर से टीबी व सोने-चांदी के जेवरात और पैसे चुरा ले जाने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर पंजीकृत किया गया था । थाना मेजा पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोगों में प्रकाश में आये 02 वांछित अभियुक्तों 1.रवि निषाद पुत्र नेब्बूलाल 2. सोनू निषाद पुत्र नेब्बूलाल को मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्र मेजा से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तों से चोरी हुये सामान के बारे मे पूछताछ करने पर बताया गया कि हम लोगों ने अपने हिस्से का सामान बेच दिया था तथा उससे प्राप्त रुपये अपने निजी जरुरत में खर्च कर लिया था अब हमारे पास कोई सामान व रुपये नही है। गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में उ0नि0 हरिओम सिंह, उ0नि0 अक्षय कुमार सिंह, का0 विकाश शर्मा ने दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

डीएम की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक

बहराइच।

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत क्रियान्वित की जा रही पाइप पेयजल योजनाओं की समीक्षा हेतु विगत दिवस कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। बैठक का संचालन करते हुए अधि.अभि. जल निगम सूरज वर्मा ने बताया कि आर.पी.डब्लू.एस.एस. अन्तर्गत अब तक 362 योजनाओं की आई.डी. बनायी जा चुकी है। डीएम ने निर्देष दिया कि समस्त ग्रामों की आई.डी. शीघ्र बनाना सुनिश्चित करें। श्री वर्मा ने बताया कि 36 राजस्व ग्राम का जल सेवा आंकलन का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है, शेष का कार्य प्रगति पर है। डीएम ने निर्देश दिया कि समस्त लक्षित ग्रामों में एक सप्ताह के अन्दर कार्य पूर्ण कराया जाय। नल जल मित्र की समीक्षा के दौरान बताया गया कि कार्यवाही प्रारम्भ करा दी गयी है तथा दो नल जल मित्र का नामिनेशन कराया जा चुका है तथा शेष की सूंची जिला पंचायत राज अधिकारी बहराइच द्वारा तैयार करायी जा रही है। इस सम्बन्ध में डीएम द्वारा अधिशासी अभियन्ता एवं जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देश दिया गया कि आपसी समन्वय स्थापित करते हुए उक्त कार्य को यथा शीघ्र पूर्ण कराते हुए पोर्टल पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें। अधि.अभि. श्री वर्मा ने बताया कि कार्यदायी फर्म मेसर्स पी.एन.सी.- एस.पी. एम. एल. (जे.वी.), द्वारा 599 नग पाइप पेयजल योजनाओं में से 75 नग पाइप पेयजल योजनाओं में शिरोपरि जलाशय के माध्यम से पानी का

संचालन किया जा रहा है जिसमें से 36 नग पाइप पेयजल योजनाओं को पूर्ण करते हुए रख-रखाव कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। वर्तमान में फर्म द्वारा जिन पाइप पेयजल योजनाओं का कार्य 90 से 80 प्रतिशत पूर्ण है उनको प्राथमिकता पर कार्य पूर्ण कराते हुए रख-रखाव में ले जानें हेतु लक्षित किया गया है। 64 नग पाइप पेयजल योजनाओं पर मार्च 2026 तक कार्य पूर्ण कराकर रख-रखाव में लानें हेतु लक्षित किया गया है। डीएम द्वारा निर्देशित किया गया कि वितरण प्रणाली बिछाये जानें हेतु खोदी गयी सड़कों को पुर्नस्थापना कार्य में विशेष ध्यान दिया जाये तथा अवशेष पाइप पेयजल योजनाओं के सत्यापन हेतु संयुक्त निरीक्षण कराया जाय। डीएम श्री त्रिपाठी ने निर्देश दिया कि पूर्ण की गयी योजनाओं के सम्बन्ध में विकास भवन में योजनाओं के संचालन का फीडबैक प्राप्त करनें हेतु एक काल सेन्टर स्थापित किया जाए तथा जिस हेतु जे.जे.एम डैशबोर्ड पर प्रदर्शित पेयजल के आंकड़ों से मिलान करते हुए यदि उसमें किसी भी प्रकार की भिन्नता प्रदर्शित होती है तो उसे ससमय निस्तारित करया जाये।

डीएम ने यह भी निर्देश दिया कि पूर्ण की गयी समस्त योजनाओं के सम्बन्ध में विकास खण्ड स्तर पर एक समन्वय बैठक आयोजित कर ली जाए जिसमें खण्ड विकास अधिकारी, जल निगम के जूनियर इंजीनियर, फर्म के ब्लाक हेड (मेनटेनेन्श हेतु नामित) बैठक करते हुए योजनाओं के संचालन/आने वाली समस्याओं के निराकरण हेतु आपसी समन्वय बनाना सुनिश्चित करें तथा प्रत्येक माह ब्लाक स्तर पर इसके सम्बन्ध में एक बैठक अवश्य आयोजित की जाय।

जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिया कि पूर्ण की गयी समस्त योजनाओं के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत स्तर पर एक समन्वय बैठक आयोजित कर ली जाए जिसमें ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम प्रधान, जूनियर इंजीनियर/जिला समन्वय कार्यालय (डी.पी.एम.यू.) के अधिकारी/कर्मचारी, मेनटेनेन्श हेतु फर्म के नामित प्रतिनिधि योजनाओं के संचालन/आने वाली समस्याओं के निराकरण हेतु आपसी समन्वय से योजना को संचालित कराएं। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी मुकेश चन्द्र, जल निगम (ग्रामीण) बहराइच के अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता व फर्मो के प्रतिनिधि तथा जिला समन्वयक कार्यालय के कार्मिक मौजूद रहे।

हम अपनी भावी पीढ़ियों के लिए कैसा भविष्य छोड़ रहे हैं?

आजाद भारत में ऐसा कोई समय याद करना मुश्किल है, जब सार्वजनिक संभाषण का स्तर इतना नीचे चला गया हो या जब नफरत,हिंसा और सांप्रदायिकता सामान्य हो गए हों। यह आभासी और वास्तविक दुनिया दोनों में हो रहा है, शायद हर चीज एक-दूसरे को बढ़ावा दे रही हो। सबसे पहले फिल्मों और टैलीविजन सीरियल्स पर नजर डालते हैं। जितनी यादा हिंसा और खून-खराबा हो रहा है, उतने ही यादा ऐसे शोज पॉपुलर हो रहे हैं, जिनमें ये सब दिखाया जा रहा है। भयानक हत्याओं, गला काटने, खून-खराबे और टॉर्चर के सीन दर्शकों को पसंद आ रहे हैं। 'एनिमल', 'तेरे इश्क में' और 'धुरंधर' जैसी फिल्में क्रूरता को एक अलग स्तर पर ले जाती हैं। इसी तरह 'पाताल लोक' जैसे टैलीविजन सीरियल्स हमारे घरों में ही खून जमा देने वाले सीन दिखाते हैं।

ऐसे लगभग सभी मामलों में, हिंसा करने वाला व्यक्ति (आमतौर पर हीरो) बिना किसी कानूनी सजा के बच जाता है। जाहिर है, ऐसे शोज की लोकप्रियता ही प्रोड्यूसर्स को क्रूरता दिखाने का स्तर बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती है। अलग-अलग उम्र के लोगों के लिए कानूनी चेतावनी और देखने पर रोक, ऐसी हिंसा का दर्शकों पर क्या असर होगा, इस पर सोचने से यादा एक फॉर्मैलिटी है। यह सब बोलने की आजादी के नाम पर हो रहा है लेकिन इससे इंसानी मानसिकता को, खासकर युवाओं और आसानी से समझ में आने वाले लोगों को, जो नुकसान हो रहा है, वह बहुत यादा है और लंबे समय तक रहेगा। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि समाज में भी नफरत, हिंसा और सांप्रदायिकता सामान्य होता जा रहा है। हमारे राजनीतिक नेता समाज में जहर फैलाने में सबसे आगे हैं, जबकि न्यायपालिका और मीडिया आसानी से नजरें फेर रहे हैं और ऐसी आदतों पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक छोटा वीडियो क्लिप वायरल हुआ। इसमें असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा बंदूक पकड़े हुए एक खास कम्युनिटी के लोगों के समूह पर गोली चलाते हुए दिख रहे थे। यह वीडियो क्लिप किसी और ने नहीं, बल्कि असम में भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक मीडिया हैंडल ने जारी किया था। क्लिप का टाइटल 'प्वॉइंट ब्लैंक शॉट' था और उसमें लिखा था 'नो मर्सी'। सोशल मीडिया पर हंगामा मचने के बाद, पार्टी की असम इकाई के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से क्लिप हटा दी गई, लेकिन उतनी ही बुरी बात यह थी कि मुख्यमंत्री या पार्टी के किसी भी नेता ने वीडियो के कंटैंट के लिए माफी मांगने या उसकी बुराई करने से इंकार कर दिया। सरमा ने यह अजीब दलील दी है कि उन्होंने 10 सैकेंड की क्लिप 'नहीं देखी', जबकि यह सोशल मीडिया पर लगातार मौजूद है। यह साफ है कि उन्हें इतने नफरत भरे और सांप्रदायिक वीडियो के लिए कोई अफसोस नहीं है।

यह वही मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने हाल ही में लोगों से कहा था कि अगर मुस्लिम रिक्शा चालक 5 रुपए मांगें तो उन्हें सिर्फ 4 रुपए देकर उन्हें वित्तीय नुकसान पहुंचाया जाए। उन्हें लगता है कि अवैध प्रवासियों को राय छोड़ने के लिए मजबूर करने का यही एकमात्र तरीका है! उनकी अपनी सरकार की घुसपैठ रोकने या अवैध प्रवासियों की पहचान करने की जिम्मेदारी का क्या, जो एक दशक से राय पर राज कर रही है? खासकर तब, जब वही पार्टी केंद्र में भी सत्ता में है और बॉर्डर पार से अवैध प्रवासन को रोकने के लिए जिम्मेदार है। अल्पसंख्यकों पर उनके हालिया हमलों से ऐसा लगता है कि उन्हें पार्टी के राज में हुए विकास और प्रगति के आधार पर राय में आने वाले विधानसभा चुनाव जीतने का भरोसा नहीं है। उन्होंने हाल ही में अपने मुख्य कांग्रेसी विरोधी गौरव गोगोई पर भी हमला किया, उन पर और उनकी पत्नी पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया! इसके अलावा, उन्होंने उनके खिलाफ 500 करोड़ रुपए का मानहानि का केस भी किया है। सुप्रीम कोर्ट अब मुख्यमंत्री की 'हेट स्पीच' के खिलाफ एक पटीशन पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। सुनवाई के लिए पटीशन स्वीकार करते हुए, भारत के मुख्य न्यायाधीष सूर्यकांत ने मजाकिया अंदाज में कहा कि 'जैसे इलैक्शन होते हैं, वैसे ही इलैक्शन का एक हिस्सा सुप्रीम कोर्ट में भी होता है।' सुनवाई के लिए अभी कोई तारीख तय नहीं हुई है और यह उम्मीद कम है कि मुख्यमंत्री मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ अपनी बयानबाजी कम करेंगे। शारीरिक हिंसा और कम्युनलिम की खुली धमकियों का एक और मामला उत्तराखंड के कोटद्वार की घटना से जुड़ा है। फिर से एक वीडियो क्लिप घूम रही है जिसमें एक ग्रुप के लोग एक हिंदू युवक द्वारा दूसरे समुदाय के एक बुजुर्ग व्यक्ति को बचाने के लिए की गई कार्रवाई का 'बदला' लेने के लिए बस्ती की ओर मार्च करेंगे। आग उगलने वाला नेता युवाओं को एक खास दिन और समय पर बड़ी संख्या में शामिल होने के लिए उकसाता हुआ और पुलिस को उन्हें रोकने की हिम्मत करने की चुनौती देता हुआ दिख रहा है।

यह कॉलम लिखे जाने तक, न तो पुलिस और न ही न्यायपालिका ने इस धमकी पर कोई ध्यान दिया था। बड़े पैमाने पर समाज और खासकर हमारे वरिष्ठ नेताओं को, आत्ममंथन करना चाहिए और इस बात पर सोचना चाहिए कि हम अपने देश की आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसा माहौल छोड़कर जा रहे हैं।

-विपिन पब्बी

सम्पादकीय...

क्या हम महर्षि दयानंद के दिखाए हुए मार्ग पर चल पाए?

150 साल की अंग्रेजों की गुलामी और उनसे छुटकारा पाने का कड़ा संघर्ष। बहुत मुश्किल से हमारे पुरखों ने आजादी की नींव रखी, नींव की इन्हीं मजबूत ईंटों में से एक थे, आर्य समाज के संस्थापक, वेदों के पुरोधा, जगद्गुरु महर्षि दयानंद सरस्वती जी। अपने अज्ञातवास में अंग्रेजों की राजनीतिक धूर्तता और भारत के सामाजिक-आर्थिक पतन का करारा जवाब उन्होंने दिया लेकिन आज यदि हम पूछें कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी की समाज को क्या देन है, तो कुछ रटे-रटाए उत्तर मिलेंगे- उन्होंने हमें यज्ञ करना सिखाया, वेदों की ओर लौटने का संदेश दिया, चारों वेदों का भाष्य करके हमें सौंप दिया, पुरानी रूढ़ियों, आडंबरों और खोखले विचारों के खोल से निकालकर नएपन को अपनाने का संदेश दिया, वर्ण-आश्रम बताए, आर्य-अनार्य में अंतर समझाया। लेकिन एक प्रश्न मानस में उथल-पुथल मचाता है कि महर्षि दयानंद जी ने हमें ये सब क्यों बताया? निश्चित रूप से हमें उत्तम नागरिक बनाने के लिए और हममें आर्यत्व की भावना भरने के लिए। लेकिन जरा रुकिए और मनन कीजिए, क्या हम वास्तव में स्वामी दयानंद सरस्वती जी के दिखाए हुए मार्ग पर चल पाए? क्या हम अपनी नई पीढ़ियों को अछे नागरिक बना सके? क्या उन्हें वे संस्कार सिखा सके, जिनकी राह महर्षि दयानंद ने हमें दिखाई थी? प्रश्न यह भी उठता है कि हमारी संतानें आज किधर जा रही हैं? हम आर्यसमाजी तो बने, लेकिन क्या हम ईमानदार और जिम्मेदार आर्यसमाजी बन पाए? गुरु की गरिमा को चोट पहुंचाते हुए, पाश्चात्य संस्कृति के अंधानुकरण में अपनी संस्कृति को पैरों तले रौंदते हुए हम किस तरह की तरक्की की बात आज कर रहे हैं? ताक पर रखे गए रिश्ते हमारी युवा पीढ़ी के दिशाविहीन हो जाने की कहानी कह रहे हैं। पिछले दिनों किसी कोरियन ऐप के आकर्षण में बंधी 3 सगी बहनों द्वारा आत्महत्या कोई एक अकेला उदाहरण नहीं है। ऐसी हजारों घटनाएं रोज हमारे समाचार पत्रों की सुर्खियां बनती हैं। अपने माता-पिता की इछाओं और आत्मबोध से बेखबर नई पीढ़ी जरा-सी भी असफलता पाते ही हत्या और आत्महत्या जैसी प्रवृत्तियों को अपना रही है तो निस्संदेह प्रश्न उठता है कि क्या सचमुच ऐसी ही आर्य संतानें बनाने का सपना महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने देखा था? हर वर्ष महर्षि दयानंद जी का जन्म दिवस मना लेना, आर्य समाज में धूमधाम से प्रचार-प्रसार का ढिंढोरा पीटना और एक-दूसरे की प्रशंसा करते हुए आपस में सम्मान की रेवड़ियां बांट लेना क्या काफी है? क्या ऐसी छिटपुट गतिविधियों से हम देव दयानंद के बलिदान का अंश भर भी ऋण चुका पा रहे हैं? उनका सपना यदि जय-जयकार पाने का ही होता तो वह वेदों की मूल प्रतियों की खोज न करते, सत्रह बार विषपान न करते, इससे अधिक ख्याति तो ऊखीमठ के पंडितों द्वारा दिए गए महंत की गद्दी के प्रलोभन को स्वीकार करके भी मिल जाती। सुविधा संपन्न के लिए जय-जयकार पाना कोई कठिन काम नहीं है। लेकिन उनका लक्ष्य तो मानव जाति को ऊंचाई पर देखने का था। क्या हम उनके इस लक्ष्य को पूरा करने की ओर अग्रसर हैं? व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर देश और समाज के सच्चे प्रहरी बनने का कर्तव्य हम कब निभाएंगे? आइए! मनन करें कि ऋषिऋण और गुरुऋण चुकाने में कहां-कहां चूक हो रही है? शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से ऐसे सांचों का निर्माण करना नितांत आवश्यक है।

गुरु नगरी में खालिस्तानी गतिविधियों को बढ़ावा?

पंजाब जिसे गुरुओं पीरों की धरती कहा जाता और खासकर अमृतसर शहर जिसमें सिखों का सबसे पवित्र धार्मिक स्थल श्री दरबार साहिब जिसके प्रति आज सिख ही नहीं बल्कि गैर सिखों में भी पूर्ण आस्था है और देश विदेश से हजारों श्रद्धालु प्रतिदिन इस पवित्र स्थल पर नतमस्तक होकर अपना अकीदा गुरु चरणों में भेंट करते हैं, मगर वहीं कुछ कट्टरपंथी संगठन समय-समय पर खालिस्तानी गतिविधियों को बढ़ावा देकर माहौल खराब करने और समूचे संसार में सिखों की बदनामी करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। बीते दिनों जब समूचा देश गणतन्त्र दिवस का जश्न मनाने में लगा था तो उस दौरान एक बार फिर से श्री दरबार साहिब परिसर में आकर खालिस्तानी समर्थकों ने माहौल खराब करने और आपसी भाईचारे को खराब करने की मंशा से खुलेआम खालिस्तानी नारे लगाए। हैरानी तो इस बात की भी है कि प्रशासन के द्वारा इन्हें शुरूआत में ही क्यों नहीं रोका गया जिससे कहीं न कहीं पंजाब की सरकार की मंशा पर भी सवाल खड़े होते हैं। खालिस्तानी समर्थक हैरिटेज स्थल, भरावां दा ढाबा से खालिस्तानी नारे लगाते हुए श्री दरबार साहिब की ओर कूच कर रहे थे जो कि 2 किलोमीटर के करीब का रास्ता है अगर प्रशासन उन्हें वहीं रोक लेता तो शायद वह श्री दरबार साहिब परिसर में दाखिल ही न होते। अगर शिरोमणि कमेटी ने सूझबूझ से काम न लिया होता तो शायद कट्टरपंथियों और कमेटी स्टाफ में खूनी झड़प भी हो सकती थी। वैसे तो अब सभी लोग इस बात को समझ चुके हैं कि भारत का कोई भी सिख खालिस्तान का समर्थक नहीं हैं। चंद लोग ही हैं जो समय समय पर खालिस्तान के नारे लगाते रहते हैं जिसके लिए शायद उन्हें विदेशों से फंडिंग होती है। विदेशों में बैठकर गुरपतवंत सिंह पन्नू जैसे लोग हैं जो इन लोगों से ऐसा करवाते रहते हैं। दिल्ली में भी पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया जिन्हें गुरपतवंत सिंह पन्नू जैसों के द्वारा दिल्ली की दीवारों पर खालिस्तानी नारे लिखने की जिम्मेवारी दी गई थी, मगर दिल्ली पुलिस की चौकसी ने उन्हें पहले ही काबू कर लिया। पंजाब केवल एक राय नहीं, बल्कि गुरुओं की तपोभूमि, शहीदों की कर्मभूमि और मेहनतकश किसानों-मजदूरों की धरती है। इस मिट्टी ने देश को अन्न दिया, आज़ादी की लड़ाई में सबसे यादा बलिदान दिए और सीमाओं पर खड़े होकर राष्ट्र की रक्षा की, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज चंद लोग खालिस्तानी नारों के ज़रिये पंजाब के शांत माहौल को फिर से अशांत करने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली को खालिस्तान बनाने जैसे धमकी भरे ईमेल भेजकर, स्कूलों और संसद को बम से उड़ाने वाले धमकी भरे ईमेल भेजकर दहशत फैलाई जा रही है। 1980 और 90 के दशक का पंजाब आज भी लोगों के ज़हन में ज़िंदा है। बड़ी मेहनत से पंजाब ने उस अंधेरे से निकलकर दोबारा सामान्य जीवन पाया। इसका सबसे यादा नुक्सान पंजाब के युवाओं का हो रहा है। बेरोज़गारी, नशा, विदेश पलायन और भविष्य की चिंता पहले से ही उन्हें परेशान कर रही है। ऐसे में सोशल मीडिया पर भावनात्मक वीडियो, अधूरी कहानियां और भड़काऊ भाषण दिखाकर उन्हें उकसाया जाता है। टाइगर अभी जिन्दा है ~ टाइगर अभी जिन्दा है यह किसी फिल्म का डॉयलाग लग रहा होगा मगर इन शब्दों का प्रयोग शिरोमणि अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया ने जेल से बाहर आकर अपने समर्थकों का हौंसला बढ़ाने और विरोधियों को चेतावनी देने हेतु किया गया। इसमें कोई दो राय नहीं कि मजीठिया के जेल से रिहाई ने वैंटीलेटर पर जाती शिरोमणि अकाली दल को नया जीवनदान दिया है। सूत्रों की मानें तो सत्ताधारी आम आदमी पार्टी की इछा थी कि विक्रम सिंह मजीठिया को 2027 के आम चुनावों तक जेल में रखा जाए जिससे उन्हें शिरोमणि अकाली दल के खिलाफ प्रचार करने का पूरा मौका मिले। मजीठिया का संदेश अकाली कार्यकर्ताओं के लिए ऊर्जा है और आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए सीधी चुनौती। अब विपक्ष की राजनीति सिर्फ बयानबाज़ी तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि सड़क से सदन तक संघर्ष का रूप ले सकती है। पंजाब की सियासत में लंबे समय बाद ऐसा दिन आया जब एक रिहाई ने पूरे राजनीतिक माहौल में हलचल पैदा कर दी। शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता विक्रम सिंह मजीठिया की जेल से वापसी सिर्फ एक व्यक्ति की आज़ादी नहीं है, बल्कि यह उस राजनीति की वापसी है, जो आक्रामक तेवर, संगठनात्मक पकड़ और सत्ता से सीधी टक्कर के लिए जानी जाती है। मजीठिया जब जेल में थे, तब अकाली दल की राजनीति कुछ हद तक रक्षात्मक हो गई थी। पार्टी का हमला सीमित था और नेतृत्व का एक बड़ा चेहरा मैदान से बाहर था। उनकी अनुपस्थिति में अकाली दल वह धार नहीं बना पाया, जो कभी उसकी पहचान थी। अब मजीठिया की वापसी से पार्टी को फिर से आक्रामक विपक्ष की आवाज़ मिल गई है। अब तक सरकार मजीठिया की गिरफ्तारी को 'नशे के खिलाफ कार्रवाई' के रूप में पेश करती रही। लेकिन रिहाई के बाद विपक्ष इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताकर जनता के बीच ले जाएगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान के द्वारा रिहाई से पूर्व जेल में मजीठिया से मिलने पहुंचे डेरा ब्यास मुखी गुरिन्दर सिंह ढिल्लो पर जिस प्रकार तंज कसा गया उससे भी जनता काफी खफा दिखाई दे रही है। वहीं दिल्ली से शिरोमणि अकाली दल नेता परमजीत सिंह सरना ने साफ कहा कि एक धार्मिक डेरे के मुखी का जेल में मजीठिया से मुलाकात करना और बाहर आकर मीडिया से रुबरु होकर यह कहना कि वह उनके दोस्त, रिश्तेदार हैं, और बेकसूर हैं दर्शाता है कि मजीठिया ही नहीं समूचे शिरोमणि अकाली दल को बिना वजह बदनाम किया जा रहा है। गुरुद्वारा अंब साहिब जमीन बिक्री मामले में धामी की छवि धूमिल - सिख धर्म के गुरुद्वारे केवल इमारतें नहीं होते, वे आस्था, इतिहास और संगत के विश्वास का केंद्र होते हैं। लेकिन जब इन्हीं धार्मिक स्थलों की संपत्ति पर सवाल खड़े होने लगें, तो मामला केवल कागज़ों तक सीमित नहीं रहता, वह समाज की आत्मा को झकझोर देता है। मोहाली स्थित गुरुद्वारा श्री अंब साहिब की ज़मीन बेचने को लेकर उठा विवाद आज संसार भर में चर्चा का विषय बन चुका है। बताया जा रहा है कि गुरुद्वारे की बेशक़ीमती ज़मीन जिसकी कीमत करोड़ों में है उसे मात्र एक करोड़ बत्तीस लाख में बेच दिया गया और जब मामला तूल पकड़ने लगा तो अध्यक्ष हरजिन्दर सिंह धामी के द्वारा एक मैनेजर पर कार्रवाई कर मामला शान्त करने के प्रयास किए गए जिससे इस धांधली के छिंटे उनके दामन पर भी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। हर कोई सोचने को मजबूर है कि किसी भी संस्था में कार्यरत किसी मुलाजिम की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि इतनी बड़ी धांधली को अंजाम दे सके जब तक उसके पीछे कोई बड़ी ताकत ना हो। इसमें भी शिरोमणि अकाली दल या शिरोमणि गुरुद्वारा कमेटी के कई बड़े नेतागण शामिल हो सकते हैं जिसकी जांच निश्चित तौर पर होनी चाहिए।

दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका, महासचिव जगदीप सिंह काहलो सहित अन्य सिख जत्थेबंदियों के द्वारा मुद्दे को गंभीरता से उठाते हुए श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार साहिब से भी गुहार लगाई गई है कि इस मामले पर कार्रवाई की जाए वहीं पंजाब सरकार को भी चाहिए कि किसी सरकारी एजेन्सी के द्वारा जांच करवाई जाए।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने वन्दना ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, साउथ पीपलथला एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार शास्त्री, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2019/08863)

चित्रकला प्रतियोगिता में छात्र-छात्राओं ने उत्साह से लिया भाग

नई दिल्ली , (साहिल गौड़) भारती व समर्पण परिवार के संयुक्त तत्वाधान मे 26वी चि त्रकला प्रतियोगिता का आयोजन नांगलोई के रेलवे स्टेशन रोड के अशोक पार्क मे किया गया, प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि स्थानीय पार्षद के पति व सामाजिक कार्यकर्ता राजेन्द्र लाठला थे,इस अवसर पर सक्षम भारतो के विनोद कालरा,नीरज शर्मा,सुभाष मलिक ,रवि रंजन की उपस्थिति उल्लेखनीय थी, कार्यक्रम की अध्यक्षता नत्थू लाल मोरवाल ने की व संचालन समर्पण के अध्यक्ष राजेन्द्र खर्रा ने किया। चित्रकला प्रतियोगिता में नर्सरी कक्षा से बाहरवी कक्षा के छात्र/छे त्राओ को चार विभिन्न वर्गों में बांट कर (नर्सरी से दूसरी कक्षा, कक्षा तीसरी से पांचवीं तक, छठवीं कक्षा से आठवीं तक,नौवी कक्षा से बाहरवीं कक्षा) आयोजन किया गया, सभी वर्गों के लिए अलग-अलग विषय निर्धारित किए गए हर वर्ग के प्रथम, द्वितिय,

तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को पुरुष्कार व प्रमाणपत्र देकर सम्मनित किया गया

इस अवसर विनोद कालरा ने सम्बोधित करते हुए सक्षम भारती के कौशल कोर्स को जानकारी देते हुए बताया कि हम बच्चों को उज्ज्वल भविष्य बनाने के लिए कार्य कर रहे है राजेन्द्र लाठला ने समर्पण परिवार की सहराना करते हुए कहा कि समर्पण परिवार छात्र /छे त्राओ की प्रतिभा को निखारने मे अहम भूमिका निभा रहा है। इस अवसर पर छात्र छे त्राओ का उत्साह देखते योग्य था अनेक प्रतियोगितात्मक ने विभिन्न विषय मे अपनी चित्रकला से कार्यक्रम मे आए लोगो का मन मनमोहन लिया,चित्रकला प्रतियोगियो के विजेताओ का चयन करने मे राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित चित्रकला अध्यापक सुरेन्द्र कुमार व सुमित ने अहम भूमिका निभाई।

कार्यक्रम मे आर्य पब्लिक स्कूल की चित्रकला अध्यापिकाओं का विशेष सहयोग रहा।

समर्पण परिवार के संस्थापक अध्यक्ष राजेन्द्र खर्रा ने प्रतियोगिता मे भाग लेने वाले सभी प्रतियोगियो को धन्यवाद करने हुए विजेताओ को इस प्रकार अपनी प्रतियोगिता को बढ़ने का आशीर्वाद दिया। प्रतियोगिता को संचालित करने में आकाश मथुर की अहम भूमिका रही। इस अवसर पर राजेश देहराण, कर्ण बामनिया,प्रवीण बैरवा,तारा चन्द बामनिया,अंजली,अनन्या, काजल,आदित, हिमांशी,करीना सहित अनेक सामाजिक कार्यकर्ता का विशेष योगदान रहा थे।

दिल्ली के आदिवासियों की अलग से जनगणना की मांग

नई दिल्ली (इंदरजीत सिंह) जातिवीर बाबा तिलका मांझी जयंती पर श्रद्धांजलि सभा आयोजन भगवान बिरसा मुंडा भवन में किया गया,कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद गजेन्द्र सिंह पटेल थे, कार्यक्रम की अध्यक्षता सौदानी आदिवासी ने की। मंच संचालन नरेंद्र मरावी द्वारा करते हुए आदिवासी के मुद्दों पर सबका ध्यान आकर्षित किया। इस अवसर पर गजेन्द्र सिंह पटेल ने तिलका मांझी को श्रद्धांजलि देते हुए दिल्ली की आदिवासियों के अस्तित्व पर सवाल उठाते हुए कहा कि दिल्ली में विभिन्न राज्यों से आकर बसे आज भी अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रहे हैं दिल्ली में बसे आदिवासियों की अब अलग से जनगणना जरूरी हो गई है जिससे आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जा सके। डॉ. पवन केरकार ने बाबा तिलका मांझी ने आजादी से पहले बसे आदिवासी

के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके योगदान को प्रेरणादायी बताया। अखिल भारतीय धानका आदिवासी समाज रंजि के संयोजक राजेन्द्र खर्रा आज भी अपनी सरकारी पहचान को तरह रहे हैं, पिछले सरकारों के सौतेले व्यवहार के कारण दिल्ली के आदिवासियों की पिछले 75 वर्षों से अलग से पहचान नहीं की गई। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के तोता राम दिल्ली में आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों हो रहे कुठाराघात की ओर ध्यान दिलाते हुए उनकी अलग से जनगणना की मांग की।सौदानी आदिवासी ने कार्यक्रम में आए सभी का धन्यवाद करते हुए दिल्ली के आदिवासियों को एकजुट होने की अपील की। कार्यक्रम का आरंभ बाबा तिलका मांझी को श्रद्धांजलि देकर किया, कार्यक्रम में जनजाति सुरक्षा मंच के श्री पी. मुर्मू,अमिताभ किशोर, सुरेश कुलकर्णी,संजय,दीपक भील सहित बड़ी संख्या आदिवासी समुदाय के लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में जनजाति सुरक्षा मंच की छाया मौंडिया प्रभारी नीतू मेघी ने सभी का आभार व्यक्त किया।

अरविंद केजरीवाल की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, बरी करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देगी ईडी

नई दिल्ली ।

राउज़ एवेन्यू अदालत ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति भ्रष्टाचार मामले में आरोप तय करने पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अदालत ने सीबीआई और आरोपियों, जिनमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और 21 अन्य शामिल हैं, की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा। विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने सीबीआई की ओर से सहायक महाधिवक्ता डी पी सिंह द्वारा दिए गए प्रतिवादों को सुनने के बाद आरोप तय करने पर फैसला सुरक्षित रखा। अदालत द्वारा 27 फरवरी को फैसला सुनाए जाने की संभावना है। सीबीआई ने पहली बार 2022 में आरोप पत्र दाखिल किया था और बाद में पूरक आरोप पत्र दाखिल किए। आरोप है कि प्रस्तावित दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति को अपने पक्ष में प्रभावित करने के लिए दक्षिण लॉबी द्वारा 100 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था। इस मामले में सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, के कविता,

कुलदीप सिंह, नरेंद्र सिंह, विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली, अरुण रामचंद्र पिल्लई, मूथा गौतम, समीर महेंद्रू, अमनदीप सिंह ढल्ल, अर्जुन पांडे, बुचीबाबू गोरनातला, राकेश जोशी, दामोदर प्रसाद शर्मा, प्रिंस कुमार, चनप्रीत सिंह रायत, अरविंद कुमार सिंह, दुर्गेश पाठक, अमित अरोरा, विनोद चौहान, आशीष माथुर और पी सरथ चंद्र रेड्डी सहित 23 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है। सीबीआई ने कहा कि साजिश के अपराध को समग्र रूप से देखा जाना चाहिए। साक्ष्यों का महत्व मुकदमे के दौरान परखा जाएगा। सीबीआई ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। एसजी डीपी सिंह और उनके वकील मनु मिश्रा ने सीबीआई का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने कहा कि सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन ने तर्क दिया कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आरोप तय करने के लिए कोई सबूत नहीं है। 17 जनवरी को वरिष्ठ वकील एन हरिहरन ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के समक्ष प्रस्तुत किया कि उनके खिलाफ कोई भी आपत्तिजनक सबूत नहीं है और उनके खिलाफ दायर आरोपपत्र पिछली आरोपपत्र की हूबहू नकल है। वे मुख्यमंत्री के रूप में अपना आधिकारिक कर्तव्य निभा रहे थे। वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि केजरीवाल अपना आधिकारिक कर्तव्य निभा रहे थे। ऐसा कोई सबूत नहीं है जो उन्हें दक्षिण लॉबी से किसी से भी पैसे लेने के अनुरोध से जोड़ता हो। पहले आरोपपत्र में और तीनों पूरक आरोपपत्रों में केजरीवाल का नाम नहीं था। उनका नाम चौथे पूरक आरोपपत्र में आया। यह भी प्रस्तुत किया गया कि चारों आरोपपत्रों का विषय पिछली आरोपपत्रों के समान ही है। यह केजरीवाल के खिलाफ आरोपों की हूबहू नकल है। बहस के दौरान, वरिष्ठ वकील ने आगे की जांच की अनुमति के मुद्दे को भी उठाया। वरिष्ठ वकील एन हरिहरन ने कहा कि आगे की जांच के लिए अदालत की अनुमति से, आरोपी के अपराध को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत होने चाहिए।

परित्यक्त नवजात को बचाने में दिखी पुलिस की मानवता

नई दिल्ली।

दक्षिण दिल्ली के जीके-2 क्षेत्र स्थित टिकोनापार्क से एक परित्यक्त नवजात शिशु को बचाकर मानवता की मिसाल पेश की है चित्तरंजन पार्क थाने की एसएचओ वंदना राव ने। मिली जानकारी के अनुसार, सुबह करीब 9:25 बजे कुछ मॉर्निंग वॉक करने वालों ने पार्क के एक कोने में एक नवजात शिशु को गंभीर अवस्था में पड़ा देखा। तत्काल इसकी सूचना चित्तरंजन पार्क थाने को दी गई। फोन मिलने के मात्र सात मिनट के भीतर एसएचओ वंदना राव स्वयं अकेले घटनास्थल पर पहुंच गईं। मौके पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि शिशु मृतप्राय अवस्था में पड़ा है। बिना समय गंवाए उन्होंने बच्चे को उठाया और आवश्यक कपड़े व अन्य जरूरी सामान की व्यवस्था स्वयं की। बच्चे की हालत अत्यंत नाजुक होने के कारण उन्होंने अन्य पुलिसकर्मियों का इंतजार नहीं किया और तुरंत उसे नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका उपचार शुरू किया गया। बाद में पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर प्रत्यक्षदर्शियों से

सीआर पार्क थाना प्रभारी वंदना राव ने बच्चे को पहुंचाया अस्पताल

पूछताछ की और इस संबंध में मामला दर्ज किया। फिलहाल शिशु वेंटिलेटर पर है और उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। स्थानीय निवासियों ने पुलिस की इस मानवीय पहल की सराहना की है।

फ्री में नहीं मिला विदेशी युवक को होटल में कमरा, फिर खुद को मार लिया चाकू; अस्पताल में भर्ती

नई दिल्ली ।दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में बिना पैसे के होटल में ठहरने नहीं देने पर एक विदेशी युवक ने खुद को चाकू मारकर घायल कर लिया। उसकी पहचान तुर्कमेनिस्तान निवासी 29 साल के जेहुन के रूप में हुई है। घटना के समय वह नशे में धुत था। होटल कर्मियों और मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मी ने उसे पास के अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। मध्य जिला पुलिस उपायुक्त अनंत मित्तल ने बताया कि अभी तक कि जांच में पता चला है कि 11 फरवरी को वह किसी नशीली चीज के नशे में खराब हालत में होटल लौटा। इस दौरान कमरे की मांग की और कहा कि उसके पास पैसे नहीं हैं और वह फ्री में रहना चाहते हैं। होटल स्टाफ ने उसकी मांग ठुकरा दी और कहा कि कोई कमरा खाली नहीं है। कमरा खाली न होने की बात बताने पर जेहुन बहुत गुस्सा हो गया। उसने अपने पास मौजूद चाकू से अपना गला काटकर खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। पुलिस मामले की जांच कर रही है

दिल्ली में 15 दिन में 800 लोग गायब? हाई कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से मांगा जवाब

नई दिल्ली ।

दिल्ली में लापता लोगों के बढ़ते मामलों को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने गंभीर चिंता जताई है. कोर्ट ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस से उनका पक्ष मांगा है. चीफ डी.के. उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने यह भी पूछा कि क्या इसी तरह की कोई याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है. वहीं मामले की अगली सुनवाई 18 फरवरी को तय की गई है. यह जनहित याचिका हृलह फ्रीडम रिक्लेम्ड की ओर से दाखिल की गई है, जिसमें दावा किया गया है कि दिल्ली में लापता लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और यह एक अभूतपूर्व संकट बन चुका है. याचिका के मुताबिक साल 2026 के पहले महीने के 15 दिनों में ही 800 से यादा लोग लापता हो गए. याचिकाकर्ता का कहना है कि व्यक्ति का मिलना भी एक अधिकार है जो संविधान के आर्टिकल 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा है. दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि पुलिस की जांच और रोकथाम व्यवस्था में ढीलापन दिख रहा है जिससे संगठित अपराध और मानव तस्करी जैसी गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकता है. दिल्ली पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक, साल 2016 से 15 जनवरी, 2026 तक कुल 2,32,737 लोग लापता हुए, जिनमें से 52,326 अब तक नहीं मिले हैं. इनमें 6,931 बच्चे भी शामिल हैं जो अब भी लापता हैं. याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि किसी व्यक्ति के लापता होने के बाद का गोल्डन ऑवर यानी शुरुआती महत्वपूर्ण समय अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है और एफआईआर दर्ज करने में देरी होती है. दिल्ली हाई कोर्ट से मांग की गई है कि हर लापता मामले में तय नियमों का सख्ती से पालन हो. साथ ही एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाने की भी मांग की गई है. जो लापता लोगों के रिकॉर्ड का मिलान अस्पतालों में अज्ञात मरीजों और मुर्दाघरों में अज्ञात शवों के डेटा से नियमित रूप से करें. मामला अब 18 फरवरी को फिर सुना जाएगा.

जनता से वादाखिलाफी... लाडली योजना बंद करने पर बीजेपी सरकार पर बरसी कांग्रेस

नई दिल्ली । दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जोरदार हमला बोला है. चांदनी चौक जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक में उन्होंने 'लाडली योजना' को बंद कर 'लखपति बिटिया योजना' शुरू करने के फैसले को राजनीतिक दिखावा करार दिया और सरकार पर जनता से वादाखिलाफी, अव्यवस्था और संवेदनहीनता के आरोप लगाए. बैठक में कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे. कांग्रेस नेताओं ने एक सुर में कहा कि दिल्ली की जनता बदलाव चाहती है और अब सिर्फ वादों से काम नहीं चलेगा. देवेंद्र यादव ने खास तौर पर 'लाडली योजना' को बंद कर 'लखपति बिटिया योजना' शुरू करने के फैसले पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि यह कदम दिखाता है कि भाजपा के पास अपनी कोई स्पष्ट नीति नहीं है. उनके मुताबिक, एक योजना को खत्म कर नई योजना का ऐलान करना राजनीतिक दिखावा है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री 1 अप्रैल से लागू होने वाली योजना की अभी से तारीफ कर रही हैं, जबकि इसका आधिकारिक लॉन्च 19 फरवरी को प्रस्तावित है और अभी तक दिल्ली का बजट भी पेश नहीं हुआ है. यादव ने इसे इवेंट मैनेजमेंट की राजनीति करार दिया और कहा कि सरकार असली काम करने के बजाय प्रचार पर यादा ध्यान दे रही है.

महिलाओं से किए वादों को लेकर घेरा

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद महिलाओं के मुद्दों पर गंभीरता नहीं दिख रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को 2500

रुपये मासिक सहायता, 500 रुपये में गैस सिलेंडर और होली-दीवाली पर मुफ्त सिलेंडर देने का वादा किया था, लेकिन अब तक ये वादे पूरे नहीं हुए. उन्होंने यह भी दावा किया कि जनवरी के पहले 15 दिनों में 800 से यादा लोगों के लापता होने की घटनाएं सामने आईं, जिनमें बड़ी संख्या महिलाओं और लड़कियों की है. यादव के मुताबिक दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक है और महिलाओं के खिलाफ अपराध कम होने के बजाय बढ़ रहे हैं. देवेंद्र यादव ने कहा कि पिछले एक साल में सरकार ने विकास और कल्याण की कई घोषणाएं कीं, लेकिन धरातल पर कोई ठोस बदलाव नजर नहीं आता. उन्होंने दावा किया कि दिल्ली का बुनियादी ढांचा कमजोर हो चुका है. उनके अनुसार अस्पतालों में मरीजों को इलाज के लिए भटकना पड़ रहा है, सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर गिर रहा है और डीटीसी बसों की संख्या कम होने से लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता है. उन्होंने कहा कि आम आदमी रोजमर्रा की सुविधाओं के लिए परेशान है, लेकिन सरकार बड़े-बड़े दावे करने में व्यस्त है.

'डबल इंजन सरकार' पर निशाना

देवेंद्र यादव ने 'डबल इंजन सरकार' के दावे पर भी सवाल उठाए. उनका कहना था कि केंद्र और राय में एक ही पार्टी की सरकार होने के बावजूद महंगाई और बेरोजगारी पर काबू नहीं पाया जा सका है. उन्होंने आरोप लगाया कि गरीबों और मजदूरों के हितों की अनदेखी की जा रही है. उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों से ग्रामीण मजदूरों के अधिकार प्रभावित हुए हैं और आम आदमी की कमर महंगाई से टूट रही है.

कार्यकर्ताओं से घर-घर पहुंचने की अपील

अपने संबोधन के अंत में देवेंद्र यादव ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे दिल्ली की सभी विधानसभाओं की कॉलोनियों में घर-घर जाकर जनता से संपर्क करें. उन्होंने कहा कि लोगों को सरकार की वास्तविक स्थिति से अवगत कराना जरूरी है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस जमीन पर सक्रिय होकर जनता की आवाज बनेगी और आने वाले समय में दिल्ली की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. बैठक में मौजूद नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी इस अभियान को तेज करने का भरोसा दिलाया.

डीडी न्यूज़ की वो शांत आवाज़ हुई खामोश, दिल्ली में समाचार एंकर सरला माहेश्वरी का निधन

नई दिल्ली। दूरदर्शन की दिग्गज समाचार एंकर सरला माहेश्वरी का दिल्ली में 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया। सार्वजनिक प्रसारक ने गुरुवार को यह घोषणा की, जिसके बाद सहकर्मियों और प्रशंसकों की ओर से श्रद्धांजलि का तांता लग गया। डीडी न्यूज़ ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि दूरदर्शन की दिग्गज एंकर सरला माहेश्वरी का 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया; वह 1980 के दशक में डीडी न्यूज़ के सबसे परिचित और प्रसिद्ध चेहरों में से एक थीं। उनकी मृत्यु पर दर्शकों, सहकर्मियों और प्रशंसकों की ओर से शोक संवेदनाओं का तांता लग गया है, जो उनकी शांत उपस्थिति और आकर्षक प्रस्तुति शैली को याद करते हैं। माहेश्वरी को दूरदर्शन की प्रतिष्ठित समाचार एंकरों में से एक माना जाता था। वे अपनी असीम शालीनता, सादगी और त्रुटिहीन हिंदी उच्चारण के लिए जानी जाती थीं, ये वे गुण थे जिन्होंने उन्हें उस दौर में विशिष्ट स्थान दिलाया जब समाचार पढ़ने में एक विशेष प्रकार का शांत अधिकार निहित था। सरला माहेश्वरी ने 1976 से 2005 तक दूरदर्शन में समाचार एंकर के रूप में कार्य किया, उनका करियर लगभग तीन दशकों तक

चला। यह वह दौर था जब दूरदर्शन भारत का प्रमुख टेलीविजन समाचार चैनल था और शाम का बुलेटिन अनगिनत घरों की दिनचर्या का हिस्सा था। दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी की पढ़ाई के दौरान आडिशन देने के बाद माहेश्वरी दूरदर्शन से जुड़ीं। उन्होंने उद्घोषक के रूप में अपना करियर शुरू किया और बाद में समाचार वाचन का काम करने लगीं। वर्षों के दौरान, उन्होंने भारतीय टेलीविजन को ब्लैक एंड व्हाइट से रंगीन प्रसारणों में बदलते देखा। दूरदर्शन के स्वर्णिम वर्षों के दौरान वे राष्ट्रीय समाचार बुलेटिनों का एक जाना-पहचाना चेहरा बन गईं और निजी 24x7 समाचार चैनलों के अस्तित्व में आने से बहुत पहले तक उनकी आवाज पहचानी जाती रही। उनकी प्रस्तुति शांत, संयमित और औपचारिक थी, जो उस दौर की पहचान थी। प्रशंसक अक्सर उनकी आवाज की स्थिरता और हर बुलेटिन में उनके द्वारा लाए गए संयम की प्रशंसा करते थे। कई लोगों ने उन्हें भारतीय टेलीविजन पर एक गरिमापूर्ण और आश्वस्त करने वाली उपस्थिति बताया है। परिवार की घोषणा के अनुसार, उनका अंतिम संस्कार 12 फरवरी, 2026 को शाम 4 बजे दिल्ली के निगम बोध घाट पर होगा।

नए भारत की नई पहचान सेवा तीर्थ, पीएम मोदी आज करेंगे राष्ट्र को समर्पित

प्रधानमंत्री सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन-1 और 2 का औपचारिक उद्घाटन करेंगे और शाम लगभग 6 बजे सेवा तीर्थ में एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 13 फरवरी, 2026 को दोपहर लगभग 1:30 बजे सेवा तीर्थ भवन परिसर के नामकरण का अनावरण करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन-1 और 2 का औपचारिक उद्घाटन करेंगे और शाम लगभग 6 बजे सेवा तीर्थ में एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। यह उद्घाटन भारत की प्रशासनिक शासन संरचना में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है और आधुनिक, कुशल, सुलभ और नागरिक-केंद्रित शासन प्रणाली के निर्माण के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। दशकों से, कई प्रमुख सरकारी कार्यालय और मंत्रालय सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में कई स्थानों पर फैले हुए खंडित और पुराने ढांचे से काम कर रहे थे। इस फैलाव के कारण परिचालन में अक्षमता, समन्वय संबंधी चुनौतियां, रखरखाव की बढ़ती लागत और काम करने के लिए अनुपयुक्त वातावरण जैसी समस्याएं उत्पन्न हुईं।

नए भवन परिसर आधुनिक, भविष्य के लिए तैयार सुविधाओं के भीतर प्रशासनिक कार्यों को समेकित करके इन समस्याओं का समाधान करते हैं। सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और मंत्रिमंडल सचिवालय स्थित है, जो पहले अलग-अलग स्थानों पर स्थित थे। कर्तव्य भवन-1 और 2 में वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, विधि एवं न्याय मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय और जनजातीय मामलों का मंत्रालय सहित कई महत्वपूर्ण मंत्रालय स्थित हैं। दोनों भवन परिसरों में डिजिटल रूप से एकीकृत कार्यालय, सुव्यवस्थित सार्वजनिक संपर्क क्षेत्र और केंद्रीकृत स्वागत सुविधाएं मौजूद हैं।
ये सुविधाएं सहयोग, दक्षता, सुचारू संचालन, नागरिकों की बेहतर भागीदारी और कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ावा देंगी। 4-स्टार GRIHA मानकों के अनुसार डिजाइन किए गए इन परिसरों में नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियां, जल संरक्षण उपाय, अपशिष्ट प्रबंधन समाधान और उच्च-प्रदर्शन वाली भवन संरचनाएं शामिल हैं। ये उपाय परिचालन दक्षता बढ़ाते हुए पर्यावरणीय प्रभाव को काफी हद तक कम करते हैं। भवन परिसरों में व्यापक सुरक्षा व्यवस्थाएं भी शामिल हैं, जैसे स्मार्ट एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, निगरानी नेटवर्क और उन्नत आपातकालीन प्रतिक्रिया अवसंरचना, जो अधिकारियों और आगंतुकों के लिए एक सुरक्षित और सुलभ वातावरण सुनिश्चित करती है।

हरियाणा जू सफारी प्रोजेक्ट पर सुप्रीम रोक

अरावली को छूने की किसी को नहीं मिलेगी अनुमति

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को हरियाणा सरकार के अरावली क्षेत्र में प्रस्तावित जू सफारी प्रोजेक्ट को अनुमति देने से इंकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट कहा कि अरावली को किसी भी कीमत पर छूने की अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की खंडपीठ ने कहा कि जू सफारी से जुड़े मामले को तब ही देखा जाएगा जब अरावली रेंज की परिभाषा विशेषज्ञों द्वारा स्पष्ट कर दी जाएगी।

अरावली छूने की अनुमति नहीं देंगे

हरियाणा सरकार की ओर से पेश वकील ने बताया कि उन्होंने प्रोजेक्ट की डीटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट को 10,000 एकड़ से घटाकर 3,300 एकड़ किया है और इसे केंद्रीय सशक्त समिति को प्रस्तुत करना चाहते हैं। खंडपीठ ने कहा हम विशेषज्ञ नहीं हैं। अरावली की परिभाषा विशेषज्ञ तय करेंगे। जब तक परिभाषा अंतिम नहीं होती, हम किसी को अरावली छूने की अनुमति नहीं देंगे। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अरावली केवल हरियाणा या राजस्थान की नहीं है, बल्कि यह कई राज्यों में फैली हुई एक महत्वपूर्ण पर्वतमाला है। उन्होंने यह भी कहा कि विशेषज्ञ समिति की राय आने के बाद ही जू सफारी प्रोजेक्ट पर फैसला लिया जाएगा।

अरावली क्षेत्र के लिए प्रोजेक्ट खतरा

पिछले साल अक्तूबर में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावित 'अरावली जू सफारी प्रोजेक्ट' को रोक दिया था। यह प्रोजेक्ट गुरुग्राम और नूंह जिलों में 10,000 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया जाना था, जिसमें बड़े बिल्लियों के क्षेत्र, पक्षियों, सरीसृपों और तितलियों के संरक्षण के लिए विशेष जोन शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में पांच सेवानिवृत्त भारतीय वन सेवा अधिकारियों और और एक पर्यावरण समूह पीपल फॉर अरावलीज द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि यह प्रोजेक्ट पहले से ही क्षतिग्रस्त अरावली क्षेत्र के लिए गंभीर खतरा है। न्यायालय ने पहले ही फैसला किया था कि अरावली हिल्स और रेंज की नई परिभाषा के अनुसार किसी भी तरह की खनन गतिविधियों की अनुमति विशेषज्ञों की रिपोर्ट आने तक नहीं दी जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय की समिति की सिफारिशें स्वीकार की थीं, जिसमें कहा गया कि अरावली हिल वह स्थल होगा जिसकी ऊंचाई स्थानीय स्तर से 100 मीटर या अधिक होगी और अरावली रेंज दो या दो से अधिक ऐसी हिल्स का समूह होगी, जो 500 मीटर की दूरी पर होंगी।

कानपुर लेम्बोर्गिनी हिट एंड रन केस में आरोपी शिवम मिश्रा को जमानत, कोर्ट ने खारिज की रिमांड

कानपुर। कानपुर लेम्बोर्गिनी कार एक्सीडेंट केस में आरोपी शिवम मिश्रा को जमानत मिल गई है. 20 हजार के मुचलके पर शिवम को बेल दी गई है. साथ ही कोर्ट ने रिमांड की मांग भी खारिज कर दी है. शिवम मिश्रा के वकील, नरेश चंद्र त्रिपाठी ने कहा कि कोर्ट ने रिमांड देने से मना कर दिया है. उन्हें (शिवम मिश्रा) अब 20,000 रुपये के अंडरटेकिंग और 20,000 रुपये के पर्सनल बॉन्ड पर रिहा किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि पुलिस सरकार के दबाव में काम कर रही थी. पुलिस ने उन्हें (शिवम मिश्रा) गलत तरीके से गिरफ्तार किया था.

-: अजित पवार के विमान हादसे पर सवाल :-

सांसद संजय राउत का केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों पर निष्पक्ष जांच न करने का आरोप

मुंबई। महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार के विमान हादसे को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने जांच पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने एनसीपी (एसपी) विधायक रोहित पवार के षड्यंत्र और तोड़फोड़ के आरोपों का भी समर्थन किया। पत्रकारों से बात करते हुए संजय राउत ने केंद्र और राज्य की जांच एजेंसियों को घेरते हुए कहा, इस राज्य और देश की जांच एजेंसियां समझौता कर चुकी हैं। चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, आईबी हो या राज्य पुलिस, जनता का इन पर से भरोसा उठ चुका है। उन्होंने कहा कि इस केंद्र सरकार के समय में बड़े मामलों की निष्पक्ष जांच नहीं होती। सरकार अपने लोगों को बचाने के लिए जांच में पक्षपात करती है। उन्होंने कहा कि जो विमान हादसे का शिकार हुआ था वह गुजरात से आया था, जिससे लोगों के मन में संदेह पैदा हुआ है। जिस विमान में अजित दादा सवार थे, वह भी गुजरात से आया था। अहमदाबाद विमान हादसे को देखिए, लगभग 300 लोग मारे गए, लेकिन उसकी जांच का क्या हुआ? कोई बता सकता है कि वह विमान कैसे गिरा? राउत ने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से भी अपील की कि वे रोहित पवार के आरोपों को गंभीरता से लें और उन्हें राजनीतिक बयानबाजी कहकर खारिज न करें। रोहित पवार तथ्यों के साथ विस्तृत जानकारी रख रहे हैं। अगर अजित दादा के निधन पर शोक सच्चा है, तो शिंदे को रोहित पवार और संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक बुलानी चाहिए। एजेंसियां काम कर रही हैं, जैसे सच से बचने का तरीका है।

किरण रिजिजू का आरोप, कांग्रेस सांसदों ने स्पीकर ओम बिड़ला के चैम्बर में घुसकर दी धमकी और गालियां

नई दिल्ली। संसद में बढ़ते तनाव के बीच, केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने गुरुवार को आरोप लगाया कि हाल ही में हुई सरकार और विपक्ष की भिड़ंत के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला के चैम्बर में घुसकर उन्हें गालियां दीं और धमकाया। मंत्री ने इस घटना का एक वीडियो भी साझा किया, जिसे उन्होंने अवैध रूप से रिकॉर्ड किया गया बताया। इस वीडियो ने संसद के भीतर एक नया राजनीतिक विवाद पैदा कर दिया है।

रिजिजू ने अपने x पोस्ट में लिखा, यह अवैध वीडियो क्लिप एक कांग्रेस सांसद द्वारा लिया गया है, जब 20-25 कांग्रेस सांसद सम्माननीय स्पीकर के चैम्बर में घुसे, उनका अपमान किया और प्रधानमंत्री को धमकाया। हमारी पार्टी हमेशा बहस और चर्चा में विश्वास करती है और कभी भी सांसदों को शारीरिक धमकी देने के लिए प्रोत्साहित नहीं करती। वीडियो में कई कांग्रेस सांसद, जिनमें अधिकांश महिलाएं हैं, स्पीकर के चैम्बर में मौजूद दिखाई देती हैं। स्पीकर अपनी कुर्सी पर बैठे हैं और कमरे में मौजूद कुछ व्यक्तियों- संभावित रूप से भाजपा सांसद या स्टाफ-के साथ गर्मजोशी से बहस कर रहे हैं। वीडियो में किरण रिजिजू भी स्पीकर के पास खड़े नजर आते हैं। यह आरोप सरकार और विपक्ष के बीच चल रहे गतिरोध के बीच आए हैं, जो तब और तेज हुआ जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पिछले सप्ताह पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे की किताब से उद्धरण देने से रोका गया था। इसके बाद उन्होंने भारत-यूएस व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री और भाजपा पर निशाना साधा।

लालू-राबड़ी और तेजस्वी को दिल्ली कोर्ट से फौरी राहत, लारा परियोजना मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुरक्षित रखा फैसला

नई दिल्ली। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लारा प्रोजेक्ट्स मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप तय करने के मुद्दे पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। यह मामला लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी प्रसाद यादव समेत 16 आरोपियों के खिलाफ है। अदालत के तीन मार्च को आदेश सुनाने की संभावना है लालू प्रसाद यूपीए की पहली सरकार में रेल मंत्री थे, तब रेलवे के ग्रुप डी में भर्तियां की गईं। आरोप है कि बिना विज्ञापन दिए भर्तियां की गईं। कई लोगों को आवेदन देने के तीन दिन के भीतर ही नौकरी दे दी गई। नौकरियों के बदले अभ्यर्थियों से घूस के रूप में जमीन ली गई। ईडी ने कहा है कि लालू परिवार को सात जगहों पर जमीनें मिलीं हैं।

महाराष्ट्र में बांग्ला भाषा बोलने के कारण प्रवासी मजदूर की हत्या की गयी- ममता

बंगाल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि उनके राज्य के 24 वर्षीय एक प्रवासी मजदूर की महाराष्ट्र में बांग्ला भाषा बोलने के कारण हत्या कर दी गई। बनर्जी ने इसे घृणा अपराध करार दिया और दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, मैं पुरुलिया में बंदवान के रहने वाले 24 वर्षीय प्रवासी मजदूर सुखेन महतो की महाराष्ट्र के पुणे में बर्बर हत्या से स्तब्ध, क्रोधित और बेहद दुखी हूं। वह अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था। उन्होंने कहा, यह घृणा अपराध से कम नहीं है। एक युवक को उसकी भाषा, उसकी पहचान, उसकी जड़ों के कारण निशाना बनाया गया, प्रताड़ित किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा, यह उस माहौल का सीधा परिणाम है जिसमें बाहरी लोगों के प्रति नफरत को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और निर्दोष लोगों को निशाना बनाया जाता है। उन्होंने आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करके दंड दिए जाने की मांग की। उन्होंने कहा, सुखेन के परिवार से मैं कहना चाहती हूं कि इस असहनीय दुख की घड़ी में पश्चिम बंगाल आपके साथ है। न्याय दिलाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी।

अखिलेश यादव बोले- ये 'डील' वो 'डाल' है, जिसको उस पर बैठने वाला ही काट रहा; ये अदृश्य जंजीर है

लखनऊ। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने गुरुवार को एक वीडियो x अकाउंट पर शेयर किया। उसके साथ लिखा- ये 'डील' वो 'डाल' है, जिसको उस पर बैठनेवाला ही काट रहा है। ये डील हमारे देश की सिर्फ खेती-मजदूरी ही नहीं बल्कि हर तरह के पैदावार-उत्पादन, काम-कारोबार और रोजगार के खिलाफ है। ये 'डील' वो 'डाल' है, जिसको उस पर बैठनेवाला ही काट रहा है। ये डील हमारे देश की सिर्फ खेती-मजदूरी ही नहीं बल्कि हर तरह के पैदावार-उत्पादन, काम-कारोबार और रोजगार के खिलाफ है। उन्होंने लिखा- ये वो अदृश्य जंजीर है जो पैसे के लालच में डूबे बिचौलियों की मानसिकतावाले खुदगर्ज भाजपाइयों को दिख नहीं रही है। जिन्होंने पहले हमारे लोगों को साक्षात जंजीर में बांधकर भेजा था वो अब उन्होंने डील का जाल फेंककर भाजपा सरकार को मजबूर कर दिया है। अब भाजपा के जो संगी-साथी कहां भूमिगत हो गये हैं जो स्वदेशी का नारा लगाते थे। आत्मनिर्भरता जगह भाजपाइयों को 'परनिर्भरता' का नारा अपना लेना चाहिए।

राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार नोटिस पर भड़की कांग्रेस, वेणुगोपाल बोले- बीजेपी में हिम्मत है तो जवाब दे

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने भाजपा को कल लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के उस भाषण पर जवाब देने की चुनौती दी है, जिसमें उन्होंने निर्मला सीतारमण द्वारा उनके सवालों का जवाब न देने की आलोचना की थी। उन्होंने किरेन रिजिजू पर संसदीय फुटेज को गलत तरीके से इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया और संसदीय कार्य मंत्री के इस कृत्य को असंसदीय बताया। उनकी यह टिप्पणी केंद्रीय मंत्री रिजिजू के उस बयान के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कल कहा था कि लोकसभा में भाजपा सदस्य कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ सदन को गुमराह करने और निराधार बयान देने के लिए, विशेषाधिकार नोटिस भेजेंगे। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए वेणुगोपाल ने कहा कि मैं उन्हें राहुल गांधी के भाषण का जवाब देने की चुनौती देता हूं। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कल अपने भाषण में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। निर्मला सीतारमण ने उनके सवालों का जवाब नहीं दिया। सदन स्थगित होने के बाद

किरेन रिजिजू ने एक वीडियो ट्वीट किया। उन्होंने संसद का वीडियो कैसे हासिल किया? संसदीय कार्य मंत्री अब असंसदीय हो गए हैं। उनका कर्तव्य संसद के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष के साथ समन्वय करना है, लेकिन वे खुद ये सब कर रहे हैं। कल रिजिजू ने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ निराधार और झूठे आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि हम सदन को गुमराह करने और निराधार बयान देने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार नोटिस दाखिल करने जा रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा में कार्यवाही और प्रक्रिया के स्पष्ट नियम हैं। जब कोई सदस्य किसी अन्य सदस्य के खिलाफ गंभीर आरोप लगाना चाहता है, तो उसे नोटिस देना होता है और आरोप को साबित भी करना होता है। उन्होंने आगे कहा कि मैंने राहुल गांधी को सदन में बुलाकर उनके द्वारा उठाए गए बिंदुओं को प्रमाणित करने का अनुरोध किया है। राहुल गांधी ने सरकार और प्रधानमंत्री के खिलाफ निराधार और झूठे आरोप लगाए हैं, उनका कहना है कि प्रधानमंत्री ने भारत और भारतीय हितों को बेच दिया है। किस आधार पर? उन्होंने बिना नोटिस दिए हरदीप सिंह पुरी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। 2026-27 के केंद्रीय बजट पर बहस के दौरान भाषण देने के बाद राहुल गांधी के सदन छोड़ने पर रिजिजू ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि भाजपा कांग्रेस नेता के «झूठ» का करारा जवाब देगी।

निशिकांत दुबे ने राहुल की सदस्यता खत्म करने के लिए प्रस्ताव पेश किया

नई दिल्ली। भाजपा सांसद डॉ. निशिकांत दुबे ने लोकसभा में एक मोशन पेश किया है, जिसमें विपक्षी नेता राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने और भविष्य में चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगाने की मांग की गई। डॉ. दुबे ने कहा सोरोस फाउंडेशन और देश को टुकड़े करने वाले ताकतों के साथ मिलकर राहुल गांधी भारत का विभाजन करना चाहते हैं। इसलिए मैंने लोकसभा के नियम 352(5) और 353 के तहत उनकी सदस्यता रद्द करने और भविष्य में चुनाव नहीं लड़ने की पाबंदी का मोशन पेश किया।

क्या है लोकसभा नियम 352 (5) और 353

लोकसभा नियम 352(5) और 353 के तहत संसद किसी सदस्य की सदस्यता रद्द करने या भविष्य के चुनावों में भाग लेने पर रोक लगाने की प्रक्रिया को अपनाती है यदि उसके कार्य संविधान और राष्ट्रीय एकता के खिलाफ हों। विशेषज्ञों के अनुसार, यह मोशन राजनीतिक रूप से संवेदनशील है और संसद में इस पर बहस और निर्णय का असर विपक्ष और राजनीतिक माहौल पर पड़ सकता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर स्पष्ट किया कि एफआईआर हो, मुकदमा दर्ज हो या Privilege प्रस्ताव लाया जाए, वे किसानों के हितों के लिए हर मंच पर लड़ेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि जो भी ट्रेड डील किसानों की रोजी-रोटी छीने या देश की खाद्य सुरक्षा को कमजोर करे, वह पूरी तरह से किसान-विरोधी है। उन्होंने चेताया कि अन्नदाताओं के हितों के खिलाफ कोई भी कदम, चाहे मोदी सरकार का हो, उन्हें समझौता करने पर मजबूर नहीं कर पाएगा। उनका संघर्ष किसानों के अधिकारों और खाद्य सुरक्षा की रक्षा तक जारी रहेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर वीडियो

जारी करते हुए कहा मोदी सरकार पर किसानों और फूड सिक्योरिटी को धोखा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि किसान भारत की नींव है और कांग्रेस हमेशा से किसानों और देश की खाद्य सुरक्षा के लिए लड़ी है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार ने अमेरिकी कंपनियों के साथ ट्रेड डील करके भारतीय किसानों को नुकसान पहुंचाया और विदेशी ताकतों के लिए कृषि मार्केट के दरवाजे खोल दिए। उन्होंने कहा कि यह कदम विशेष रूप से अडानी और अंबानी जैसे उद्योगपतियों के लिए लाभकारी है। कांग्रेस नेता ने कहा भारत के छोटे किसान उचित सहूऔर मेकेनाइजेशन के अभाव में संघर्ष कर रहे हैं, जबकि बड़े किसान और उद्योगपति सरकार की सब्सिडी और समर्थन का लाभ उठा रहे हैं। मोदी सरकार ने देश के किसानों को धोखा दिया है। राहुल गांधी ने स्पष्ट किया कि किसानों के अधिकारों के लिए कांग्रेस पार्टी और वे व्यक्तिगत रूप से पूरी ताकत से खड़े हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश जनता सच्चाई समझ रही है और हम किसानों के साथ पीछे नहीं हटेंगे।

भाजपा नेता ने दी राहुल गांधी को राष्ट्रीय सुरक्षा पर राजनीति न करने की नसीहत

इसके अलावा वरिष्ठ भाजपा नेता वानाथी श्रीनिवासन ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी से अपील की कि वे राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर राजनीति करना बंद करें और इसके बजाय रचनात्मक राजनीति पर ध्यान दें। वानाथी श्रीनिवासन ने लोकसभा में कथित रूप से एक पूर्व सेना प्रमुख की आत्मकथा को लेकर उत्पन्न हंगामे की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि कांग्रेस नेता जानबूझकर देश की सुरक्षा के साथ राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा राहुल गांधी, जिन्हें जनता ने नकार दिया है, लोकसभा में अराजकता पैदा कर रहे हैं। राजनीति में करने के लिए हजारों काम हैं, लेकिन वे अनावश्यक रूप से देश की सुरक्षा को राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। इससे उनका विपक्षी नेता का पद भी खतरे में पड़ सकता है।